24/07/2024

आकाशवाणी ईटानगर

अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तथा राज्य वित्तमंत्री चाउना मेन ने आज राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दो दशमलव शून्य आठ प्रतिशत घाटे का बजट पेश किया। श्री मेन ने विधानसभा को सूचित किया कि दो हजार सोलह से अरुणाचल प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में लगभग एक सौ पैंतीस प्रतिशत की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में एक सौ पांच प्रतिशत की वृद्धि और राज्य के बजट में एक सौ छियासी प्रतिशत का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य की अनुमानित कुल प्राप्तियां पैंतीस हजार आठ सौ चालीस दशमलव सात नौ करोड़ रुपये हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बीस दशमलव आठ पांच प्रतिशत से अधिक है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का बजट विकास के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों - स्वस्थ मानव संसाधन, मजबूत बुनियादी ढांचा और जीवंत अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। अरुणाचल की संसाधन स्थिति पर बोलते हुए, श्री मेन ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के लिए केंद्रीय करों का हिस्सा उन्नीस प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि 2024-25 के बजट अनुमान के लिए राज्य के अपने संसाधन चार हजार सोलह दशमलव सात एक करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में सत्रह दशमलव तीन पांच प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार इस वित्तीय वर्ष में राज्य के अपने संसाधनों को बढ़ाने पर अधिक काम करेगी और ध्यान केंद्रित करेगी।

0000000000000000000000

सरकार ने कैंसर की दवाओं की सामर्थ्य में सुधारने के लिए इन दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में प्रस्तावित केंद्रीय बजट 2024-25 में तीन अतिरिक्त कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से देश के सत्ताईस लाख कैंसर रोगियों को लाभ होगा। मंत्रालय ने आगे बताया कि वित्त मंत्री ने एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर सीमा शुल्क दरों में भी संशोधन किया है। इन संशोधित दरों से कम लागत पर घटक उपलब्धता को बढ़ाकर एक्स-रे मशीन उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इस बीच, यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने केंद्रीय बजट की सराहना की है और कहा है कि उद्घाटन बजट भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के साथ घरेलू उपभोक्ताओं और विदेशी निवेशकों दोनों का समर्थन करता है। फोरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारत सरकार को 2024-25 के लिए एक सराहनीय केंद्रीय बजट पेश करने के लिए बधाई दी।

0000000000000000000000

सरकार ने आज स्पष्ट किया कि मेडिकल परीक्षा को लेकर विवादों के बीच फिलहाल NEET (UG) को बंद करने और राज्यवार प्रवेश परीक्षाएं बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। यूजीसी (नेट) परीक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि इस साल जून में आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अब यह निर्णय लिया गया है कि इसे इक्कीस अगस्त से चार सितंबर दो हजार चौबीस के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित किया जाएगा।

0000000000000000000000

सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उनतीस जुलाई से तीन अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। यह पहल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के पचहत्तरवें वर्ष में मील का पत्थर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन नागरिकों से इस पहल से लाभ उठाने की अपील की है जिनके मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं।

0000000000000000000000

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार फर्जी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे देश के लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार पैदा करने की क्षमता है। उन्होंने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार के पास विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए वैधानिक और संस्थागत तंत्र हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए नवंबर 2019 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत एक फेक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 2021 से 2024 तक भारतीय प्रेस परिषद ने महाराष्ट्र राज्य के संबंध में फर्जी खबरों की पांच शिकायतों का निपटारा किया है।

0000000000000000000000

भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में □सका योगदान पच्चीस प्रतिशत है। देश में दूध उत्पादन पिछले नौ वर्षों से लगभग छह प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जबकि विश्व दूध उत्पादन दो दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि देश में दूध की खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा उनकी उत्पादन लागत और बाजार की ताकतों के आधार पर तय किए जाते हैं।

000000000000000000000000

पापुम पारे जिले के महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सागाली में योजना के तहत "बेटी जन्मोत्सव" का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए जिला आईसीडीएस सेल की उप निदेशक पापुम पारे ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और □सके लाभों पर प्रकाश डाला। महिला प्रतिभागियों को महिला केंद्रित केंद्रीय/राज्य योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी।

उन्होंने आगे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम दो हजार बारह (POCSO), घरेलू हिंसा अधिनियम दो हजार पांच के तहत प्रावधानों पर प्रकाश डाला और सभी से चा□ल्ड हेल्प ला□न 1098 पर डायल करके संबंधित अधिकारियों से सहायता लेने का आग्रह किया जो आवश्यकता पड़ने पर 24×7 उपलब्ध है।

00000000000000000000000